सरकारी और अन्य संस्थाओं पर भारी धनराशि बकाया है, यदि हां, तो यह राशि कितनी है ; और

(ङ) क्या यह भी सच है कि विगत कुछ वर्षों के दौरान प्रशासनिक व्यय में 200 प्रतिशत वृद्धि हुई है जबकि विद्युत और कोयले के क्रय मूल्यों में क्रमश: 106 प्रतिशत और 122 प्रतिशत वृद्धि हुई है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगैया नायडू) : (क) से (ङ) वर्ष 1992-93 के दौरान डेसू द्वारा 264.42 करोड़ रु० के घाटे का अनुमान लगाया गया है। 1991-92 के दौरान डेसू की अनन्तिम पारेषण एवं वितरण हानियां 22.50% थी जोकि राष्ट्रीय औसत के सन्दर्भ में तुलनीय है। उपर्युक्त हानियों को कम करने हेतु डेसू द्वारा तकनीकी एवं बाध्यकारी दोनों प्रकार के उपाय किए जा रहे हैं। 31-3-92 की स्थिति के अनुसार, डेसू द्वारा विभिन्न सरकारी निकायों एवं अन्य संस्थानों/उपभोक्ताओं से लगभग 869 करोड़ रु० की राशि वसूल की जानी है। वर्ष 1991-92 में, प्रशासनिक व्यय सहित डेसू के राजस्व व्यय में 1989-90 के दौरान व्यय की तुलना में केवल 33% की वृद्धि हुई जोकि निवेश संबंधी लागत और उपभोक्ताओं/प्रचालनात्मक कार्यकलापों की संख्या में कुल मिलाकर वृद्धि को ध्यान में रखते हुए उचित सीमा में है।

बिहार में नई विद्युत परियोजनायें

2627. श्री शंकर दयाल सिंह : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में नए विद्युत केन्द्र स्थापित किए जाने के संबंध में बिहार सरकार से प्राप्त कितने प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के पास विचारार्थ लंबित हैं; और

(ख) केन्द्रीय सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है और सरकार कितने प्रस्तावों को कब तक मंजूरी देने का विचार रखती है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगैया नायडू) : (क) और (ख) बिहार की निम्नलिखित दो परियोजनायें तकनीकी आर्थिक स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के जांचाधीन है :—

क्र सं०	स्कीम का नाम	क्षमता (मे०वा०)
1	चांडील टी पी० एस०	2×250
2	मुजफ्फरपुर टी० पी० एस० विस्तार	2×250

परियोजना प्राधिकारियों द्वारा परियोजनाओं के लिए सभी आवश्यक निवेशों तथा स्वीकृतियों को सुनिश्चित कर दिए जाने के पश्चात् ही इन परियोजनाओं के लिए तकनीकी आर्थिक स्वीकृति प्रदान किए जाने पर विचार किया जा सकेगा।

Foreign and Domestic Investment in Power Sector

2628. SHRI KRISHNA KUMAR BERLA; Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Central Government have received over 40 proposals for investment in power sector both from the foreign and domestic companies;

(b) if so, what are the names of the companies with respect to their investment for respectve capacity;

(c) the total investment that is visualised in these power projects;

(d) the number of projects that have already been granted Government's approval;

(e) what are the reasons for which the other projects have not yet been granted clearance; and

(f) by when the' proposals for re-maining power projects will be cleared?